मोदी ने लांच की कौशल विकास योजना

आइआइटी नहीं, आइटीआइ की जरूरत : प्रधानमंत्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जमीनी स्तर पर कुशल मानव शक्ति के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' की शुरुआत की। इसके तहत युवाओं को व्यावसायिक व तकनीकी ज्ञान के रूप में कौशल विकास की शिक्षा दी जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, 'मानव संसाधन का केंद्र बने भारत। इस सदी की सबसे बड़ी जरूरत आइआइटी नहीं, बल्कि आइटीआइ है।'

प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को 'नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन डॉक्यूमेंट' जारी कर कहा, 'कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रम की योजनाओ से करीब 40 करोड़ युवाओं को वर्ष 2022 तक प्रशिक्षित किया जाएगा।' उन्होंने कार्यकुशलता और दक्षता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि देश ने कौशल भुला दिया। चीन ने अपनी पहचान 'निर्माण के केंद्र' के रूप में बनाई है। हम भी 'मानव संसाधन केंद्र' के रूप में उभर सकते हैं। भारत विश्व के मानव संसाधन की जरूरत को पूरा कर सकता है क्योंकि भारत युवा देश है। हमें इस दिशा में अभी से कदम बढ़ाने चाहिए। हम चाहते हैं कि नौजवानों को नए अवसर मिलें। दुनिया में नौकरियों का बहुत बड़ा बाजार है। ऐसे में हम अगर भविष्य की ओर निगाह रखकर संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करें तो भारत दुनिया को करोड़ों कुशल कामगार मुहैया करा सकता है। सरकार इन युवाओं को कौशल प्रमाण पत्र देगी। भारतीय नौजवानों के पास जो ताकत है। देश के आइआइटी जैसे संस्थान का दुनिया लोहा मानती है। पूरे विश्व को हमारी जरूरत होने वाली है।

नई दिल्ली में स्किल इंडिया अभियान के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री। जगदीश यादव

मोदी मंत्र

- मानव संसाधन का केंद्र बने भारत
- आठ हजार रुपए प्रति माह का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा

रेलवे देगा सुविधाएं

रेलवे व कौशल विकास मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के अवसर पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, रेलवे देश में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्टेशनों पर खाली पड़ी जगहों या कम इस्तेमाल वाली जगहों, वर्कशाप, रेलवे स्कूलों और प्रशिक्षण संस्थानों को इस मद में उपलब्ध कराएगी।

कांग्रेस ने कहा, हमारी है योजना

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के 'स्किल इंडिया अभियान' पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भी संप्रग सरकार की एक योजना की री पैकेजिंग है। जबकि, पार्टी मीडिया विभाग प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को संप्रग से आगे सोच पाने में नाकाम बताया।

यह है जरूरत

वर्ष 2022 तक देश में 40 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। जबकि, इसी समय सीमा में 29.8 करोड़ की मौजूदा कामगार शक्ति को भी अतिरिक्त कौशल विकास शिक्षण की आवश्यकता होगी। यही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है।

34 लाख बेरोजगारों को कर्ज

इस अभियान के तहत मोदी सरकार ने देश में 'स्किल इंडिया' के तालमेल के लिए पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट पालिसी जारी की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल ऋण योजना के तहत 5 साल में 34 लाख कुशल बेरोजगारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।

आइटीआइ में 10 हजार नौकरियां

योजना से व्यापारिक कंपनियां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों 'आइटीआइ' के छात्रों को दस हजार से अधिक नौकरियों की पेशकश करेंगी। एनएसडीसी के प्रबंध निदेशक और सीईओ दिलीप शेनाय ने कहा, 'आइटीआइ से पास होकर निकले विद्यार्थियों को बाश, टाटा मोटर्स, मारुति, रिलायंस जैसी कंपनियों की ओर से नौकरी की पेशकश होगी।'